टाइटल कोड - MPHIN37675
Email- haldharkisankgn@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

संपादक - विवेक जैन

वर्ष 01 अंक 08 | अक्टुम्बर 2022 | पृष्ठ-8 मूल्य -5.00 रुपये

कीटनाशकों की ऑनलाईन बिक्री और अनुपातिक उर्वरक वितरण व्यवस्था हो बंद

कृषि आदान व्यापारियों के प्रांतीय अधिवेशन में पारित किए प्रस्ताव

कृषि आदान व्यापारियों का प्रांतीय अधिवेशन भोपाल में आयोजित किया गया। इसमें कीटनाशको की ऑनलाईन बिक्री पर रोक और अनुपातिक उर्वरक वितरण व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार यह जायज मांगें नहीं मानती है तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे।

हलधर किसान, भोपाल। ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस अधिवेशन में प्रदेशभर के 400 से अधिक व्यापारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि कलंत्री ने प्रदेश में कृषि आदान विक्रेता संघ की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि व्यापारियों के हित में एसोसिएशन हमेशा खड़ा है। ऑल इंडिया संघ आपकी हर मांग दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों तक मजबुती के साथ पहुंचाकर पूरी करवाने का प्रयास करेगा। विशेष अतिथि के रुप में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश संगठन जो भी मांगें कर रहा है वह जायज है।

स्वागत भाषण देते हुए प्रदेश के संगठन मंत्री विनोद जैन खरगोन ने कहा कि कई मामलों में शासन की नीति, नियम भेदभावपूर्ण नजर आते है। दुकानदार कंपनियों से खरीदा गया, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक का विक्रय करता है, जो कि नियमानुसार कृषि विभाग सेम्पल सरकारी लेब में टेस्ट होता है। ऐसी स्थिति में सेंपल फेल होने या अमानक नमूने आने पर विक्रेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है जो सरासर गलत है। जबकि मार्कफेड और सहकारी समितियों पर अमानक आदान आने पर उनके खिलाफ नहीं कि जाती। इस भेदभाव के खिलाफ लंबे समय से संघ संघर्षरत है। ऐसे मामलों में विभाग या प्रशासन कंपनी पर कार्रवाई करें न कि दुकादार पर।

इन प्रस्तावों पर बनी सहमति

अधिवेशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा की जा रही खाद बीज कीटनाशक की खरीदी बिक्री का देशव्यापी विरोध एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुपातिक उर्वरक वितरण व्यवस्था के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार से मांग की गई है कि वह तत्काल ही इन दोनों प्रस्तावों पर संगठन की भावनाओं का सम्मान करते हुए आदेश पारित करें ताकि प्रदेश में कृषि आदान व्यापार सुगमता से किया जा सके। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि संगठन के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही कृषि मंत्री कमल पटेल एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर इसे समाप्त करने की मांग करेगा और यदि सरकार द्वारा इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो न्यायालय की शरण लेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह राजपूत प्रदेश में संगठन द्वारा पिछले 3 सालों में की गई गतिविधियों की जानकारी दी। संचालन मप्र कृषि आदान विक्रेता संघ के सचिव संजय रघुवंशी ने किया एवं आभार प्रदर्शन प्रणीत समैया ने माना। इस प्रादेशिक सम्मेलन में व्यापारियों ने भी व्यापार में आ रही समस्याओं, परेशानियों को मंच पर रखा, जिसका संगठन एकता से हल करने का आश्वासन दिया गया।

संक्रमित गायों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग से हुआ खुलासा

तीन साल में सात गुना जानलेवा हुआ लंपी वायरस

हलधर किसान।
(9826225025)

देश के लाखों गोवंश को अपनी चपेट में लेने वाला लंपी वायरस बीते तीन साल में न सिर्फ सात गुना अधिक जानलेवा हुआ है बल्कि इसके 39 स्वरूप दुनिया में और किसी भी देश से नहीं मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में लंपी का स्वरूप चीन, नेपाल, भूटान, वियतनाम और म्यांमार की तुलना में ज्यादा घातक है। यह खुलासा लंपी वायरस संक्रमित छह गायों से लिए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में हुआ है। राजस्थान सरकार और नई दिल्ली स्थित आईजीआईबी के वैज्ञानिकों ने मिलकर यह जांच पूरी की है। आईजीआईबी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. विनोद स्कारिया ने बताया कि लंपी वायरस पूरी दुनिया के लिए नया नहीं है। 2019 में यह सामने आया था, लेकिन तब मृत्यु दर शून्य थी जो आज 7.1 फीसदी से अधिक है।

उन्होंने बताया कि कोरोना की तरह लंपी वायरस को लेकर भी वैश्विक स्तर पर जेनबैंक नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां अलग.अलग देशों से वायरस के जीनोम साझा किए जाते हैं। जब राजस्थान से सैंपल लेने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद जीनोम से मिलान किया तो पता चला कि दुनिया भर में लंपी वायरस के 57 स्वरूप मौजूद हैंए जिनमें से 47 स्वरूप नोबल पाए गए जो सिर्फ भारतीय गोवंश में ही थे। जब इस पर और अधिक ध्यान दिया गया तो आठ इन्सानों के लिए घातक नहीं मिले। ऐसे में सिर्फ भारत में मौजूद 39 स्वरूप चिंता का कारण बने हुए हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण बना घातक

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह एक पॉक्स वायरस है जो 1980 के दशक कैप्री पॉक्स वायरस नामक वंश से जुड़ा था, लेकिन अब इसका स्वरूप काफी जोखिम भरा है। सीधे तौर पर कहें तो यह भी जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण है।

डेयरी आजीविका पर गहरा संकट

आईजीआईबी के प्रमुख शोधकर्ता डॉ. श्रीधर शिवसुब्बू ने कहा कि दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल होने के नाते हमारे यहां लंपी वायरस का यह असर काफी गंभीर हो सकता है। इससे न सिर्फ कृषि अर्थव्यवस्था, बल्कि डेयरी आजीविका पर भी गहरा संकट पड़ सकता है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अफ्रीका में पैदा हुई यह बीमारी अप्रैल में पाकिस्तान के रास्ते भारत आयी थी। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गायों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अन्य रोग आक्रमण करते हैं।

बीमार गाय.भैंस का दूध पी लिया तो क्या होगा ?

डॉक्टरों के अनुसार अभी तक की स्टडी में लंपी वायरस से इंफेक्टेड पशु का दूध पीने से इंसान पर असर का मामला सामने नहीं आया है। इसका बड़ा कारण है कि हम दूध को गर्म करके ही पीते हैं। गर्म करने पर दूध में मौजूद बैक्टीरिया व वायरस नष्टहो जाते हैं। साथ ही ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा एसिड होता है, जो खुद ही ऐसे वायरस को खत्म कर देता है। हालांकि बीमार पशु का दूध पीने पर बछड़े जरूर संक्रमित हो सकते हैं। वहीं इंसान भी बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने से प्रभावित हो सकते हैं।

बीमारी के रोकथाम एंव नियंत्रण के उपाय

यह बीमारी एक संक्रामक रोग विषाणु जनित बीमारी है। यह बीमारी गोवंशीय एंव महिषवंशीय पशुओं में पायी जाती है। इस रोग का संचरण, फैलाव, प्रसार पशुओ में मक्खी, चिचडी एंव मच्छरों के काटने से होता है। इस बीमारी से संक्रमित पशुओ में हल्का बुखार हो जाता है। पूरे शरीर पर जगह.जगह गांठे उभर आती है। अगर आपका पशु इस बीमारी से ग्रसित हो गया है तो इस बीमारी से ग्रसित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। पशुओं को मक्खी, चिचडी एंव मच्छर के काटने से बचाने किस दिशा में काम करें। यही नहीं पशुशाला की साफ. सफाई दैनिक रूप से करें और डिसइन्फैक्शन का स्प्रे करते रहें। संक्रमित पशुओं को खाने के लिए संतुलित आहार तथा हरा चारा दें। अगर इस बीमारी से किसी की मौत हो जाती है तो मृत पशुओ के शव को गहरे गड्ढे में दबा दें।

दें यह औषधियां

लंपी संक्रमण से बचाने के लिए पशुओं को आंवला, अश्वगन्धा, गिलोय एवं मुलेठी में से किसी एक को 20 ग्राम मात्रा में गुड़ मिलाकर सुबह शाम लड्डू बनाकर खिलाएं। तुलसी के पत्ते एक मुट्ठी, दालचीनी 05 ग्राम सोंठ पाउडर 05 ग्राम, काली मिर्च 10 नग को गुड़ में मिलाकर सुबह शाम खिलाएं। संक्रमण रोकने के लिए पशु बाड़े में गोबर के कण्डे में गूगल, कपूर, नीम के सूखे पत्ते, लोबान को डालकर सुबह शाम धुआँ करें। पशुओं पशुओं के स्नान के लिए 25 लीटर पानी में एक मुट्ठी नीम की पत्ती का पेस्ट एंव 100 ग्राम फिटकरी मिलाकर प्रयोग करें। घोल के स्नान के बाद सादे पानी से नहलाएं

राजस्थान में सबसे ज्यादा 60 हजार गायों की मौत

गौरतलब है कि राजस्थान में लंपी वायरस की वजह से बीते तीन महीने में 60 हजार से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। वहीं 8 लाख गोवंश लंपी से संक्रमित हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 22 जिलों में लंपी चर्म रोग फैल चुका है। लंपी वायरस से हुई बड़ी संख्या में मौत की वजह से प्रदेश में दूध का उत्पादन भी घट गया है। दूध की कमी से कई जिलों में इसके दाम बढ़ गए हैं।

राजस्थान सरकार भी अब लंपी वायरस को लेकर और अधिक गंभीर है। यहां पशुओं की देखभाल के लिये नए पशु चिकित्सा केंद्र खोले जा रहे हैं। पशु चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों की भर्ती भी की गई है। 200 पशु चिकित्सक अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस और 300 पशुधन सहायकों की भर्ती की जा रही है। इतना ही नहीं, अब राज्य सरकार 500 से अधिक पशु एम्बुलेंस भी खरीदने जा रही है, जिसके लिए विधायक कोष से जल्द ही अनुमति मिलने की उम्मीद है। इसकी परमिशन मिलते ही पशु एम्बूलेंस की खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

संपादकीय...

देश को जरूरत है सदाबहार क्रांति की

अच्छी नस्ल के बीजों एवं कृषि की नई व्यवस्थाओं ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि की है। कृषि उत्पादन की प्रगति के आंकड़ों पर यदि नजर डाली जाए तो हम देखते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस सब का श्रेय देश के किसानों एवं वैज्ञानिकों को जाता है कि उन्होंने बढ़ती जनसंख्या और घटती हुई कृषि उपयोगी भूमि के बावजूद खाद्यान्न में आशातीत बढ़ोतरी की है। हरित क्रांति का प्रभाव चावल गेहूं आदि कुछ खास फसलों में उत्पादन क्षमता के बीजों के प्रयोग एवं रसायनों के प्रयोग के कारण उत्पादन में सुधार के रूप में रहा है लेकिन उसके बावजूद हर प्रांत की वैज्ञानिकों द्वारा अब कुछ खामियां देखी गई है जिस पर सचेत होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।

प्रयास इस बात का होना चाहिए कि हमारे किसानों को अंतरराष्ट्रीय मूल्यावस्था का लाभ मिले और उनकी आय में वृद्धि हो, हमारे किसान अब अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर माल भेज सकें एवं अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चा माल खरीदें। यह एक बहुत दूर की सोच है। वर्तमान में जरूरत है कि किसानों को संबल प्रदान करने की व असिंचित क्षेत्रों एवं अल्प शिक्षित क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इतने वर्षा के बावजूद भी अभी भी खेती सिंचित पर आधारित है इसके लिए प्रयास होने चाहिए कि हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर ध्यान दें और वह अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएं जिससे लघु एवं सीमांत किसान भी लाभान्वित हो सके इस बार मानसून की कृपा से किसानों उत्पादन में काफी सहारा मिला है जिससे भारतीय कृषि के लिए सुखदायक और लाभदायक माना जा सकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा कृषि अनुसंधान शिक्षा और प्रसार का कार्य नई ऊंचाइयों पर दिखाई दे रहा है साथ ही परिषद ने उन तमाम प्रयासों को गद्दी है जिनसे कृषि अनुसंधान और किसानों के बीच रिश्ता मजबूत हो सके इसके लिए हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से भारतीय कृषि में कई बदलाव किए जा रहे हैं इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने किसान हित में कई निर्णय लेकर कृषि को एक नई दिशा देने का कार्य किया जिससे देश में सदाबहार क्रांति को लाया जा सके। देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उन तमाम प्रयासों को गति दी जिनसे किसान दूर था। संस्थान और किसानों के बीच रिश्ता मजबूत होता दिखाई दे रहा है। देश के कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है और लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक संचार सुविधाओं से जोड़ दिया गया है ताकि किसानों तक सूचनाएं तुरंत और कुशलता पूर्वक पहुंचाई जा सकेण् इसके साथ ही अधिकतर कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से मोबाइल सलाहकार सेवा प्रारंभ की गई है, जिसमें किसानों के मोबाइल फोन पर मौसम बाजार तथा कृषि क्रियाओं संबंधी नवीनतम जानकारी को पहुंचाया जा रहा है दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी नई पहल की गई है। इसके माध्यम से किसानों को खेतों पर अधिक से अधिक प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे किसानों को देख कर नई तकनीकों से रूबरू हो और उसको अपने खेतों पर अपनाएं जिससे देश के दलहन उत्पादन को बढ़ाया जा सकेण्परिषद का प्रयास है देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गुणवत्ता युक्त और अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित कर किसानों तक पहुंचाई जाएण् इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए परिषद ने विभिन्न सुधरी हुई किस्में को किसानों को बोने के लिए जारी की है।

एनजीटी ने हरियाणा सरकार पर लगाया 100 करोड़ का जुर्माना

हलधर किसान।
(98262 25025)
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा में पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान के लिए हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पर्यावरण मुआवजे के रूप में 100 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया।

कमेटी रियायत समझौते के अनुसार लगे ठेकेदारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकती है और यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अपेक्षित प्रदर्शन करने में विफल रहा हैए हो तो कमेटी ठेकेदारों को बदलने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती हैए जैसा कि एनजीटी द्वारा पहले देखा गया था।

एनजीटी ने नोट किया कि एक ही मुद्दे से संबंधित मामले यानी पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य और आसपास के वन क्षेत्रों के पूर्वाग्रह के लिए विरासत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट डंप साइटों को संभालने और निपटाने के लिए पर्यावरणीय मानदंडों को बनाए रखने में विफलता दिखी। विचाराधीन डंप साइट गुरुग्राम में बांधवारी लैंडफिल साइट है, जहां वर्षों से लगभग 33 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरा डंप किया जाता है।

ट्रिब्यूनल एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि एक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना विकसित की गई है और एक चीनी कंपनी . ईको.ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2017 में एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था।

हालांकि, उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं, कचरे को जलाया जा रहा है, जिससे भारी वायु प्रदूषण हो रहा है, जिसमें न केवल निवासियों को प्रभावित करने की क्षमता है बल्कि असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की 193 प्रजातियांए बड़ी संख्या में औषधीय पौधे और 80 से अधिक प्रजातियां हैं। तितलियों की प्रजातियां, काला हिरन, गोल्डर सियार और तेंदुआ। ग्रीन कोर्ट ने कहा कि राज्य पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन के प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करके पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बाध्य है। ट्रिब्यूनल ने 23 सितंबर को निर्देश पारित करते हुए यह भी कहा, आपातकालीन स्थिति के संबंध में राज्य के अधिकारी यूजर्स चार्ज के भुगतान पर अस्थायी अवधि के लिए लागू कानून के अनुसार निकटतम उपलब्ध भूमि का उपयोग करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी संयंत्र को स्थापित करने की आवश्यकता है जिसके लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता है, तो ऐसे पौधों से पर्यावरण को लाभ होगा, ईसी के अनुदान की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वन, वन्यजीव और जल निकायों के संबंध में सभी पर्यावरणीय मुद्दों का पालन किया जा सकता है।

एनजीटी ने आगे कहा कि बंधवारी स्थल जो पहले से ही कई वर्षों से अस्तित्व में है और 10 एकड़ भूमि जिसे पहले ही मंजूरी दे दी गई है, का उपयोग स्थानीय निकायों के अपशिष्ट उत्पादन को संभालने के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए किया जा सकता है। भूमि की अनुपयुक्तता के मामले में एंए वैकल्पिक व्यवस्था का पता लगाया जाना चाहिए। समिति कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदूषण में योगदान करने वालों से मुआवजे की वसूली के लिए वैधानिक नियामकों के साथ समन्वय करने के लिए स्वतंत्र होगी। एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि समिति को तीन महीने के भीतर पर्याप्त प्रगति के साथ छह महीने के भीतर मामले में सार्थक प्रगति हासिल करने की उम्मीद है।

मप्र में साढ़े 3 लाख मीट्रिक टन की मूंग-उड़द की खरीदी, किसानों को 1415 करोड़ रुपए का किया भुगतान

हलधर किसान। (98262 25025)
मप्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द का लक्ष्य से अधिक उपार्जन किया है। अबतक साढ़े 3 लाख मीट्रिक टन की खरीदी कर किसानों को 1415 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। यह जानकारी मूंग और उड़द के उपार्जन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में किसानों को उपार्जित फसल की राशि के भुगतान किए जाने की भी समीक्षा की। इस दौरान जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 32 जिलों में मूंग और 10 जिलों में उड़द की खरीदी की जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश के 2 लाख 34 हजार 772 किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है। जिसमें अब तक एक लाख 46 हजार 886 किसानों से मूंग का उपार्जन किया जा चुका है।

फाईल फोटो

बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि केंद्र सरकार के निर्देश मुताबिक प्रतिदिन हर किसान से 40 क्विंटल मात्रा का उपार्जन किया जा रहा है। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं। उनमें 2507 करोड़ 12 लाख रुपए की मूंग खरीदी की जा चुकी है। जिनमें से मध्य प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य पर बेची के फसल के लिए 1415 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में इस साल मूंग और उड़द की खरीदी के लिए 370 खरीदी केंद्र बनाए गए थे। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 .23 के लिए मूंग खरीदी के 2 लाख 75 हजार 645 मीट्रिक टन उपार्जन के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जिसके मुकाबले मध्यप्रदेश में अब तक तीन लाख 44 हजार 622 मीट्रिक टन मूंग उपार्जन किया गया है।

नर्मदा पुरम, सागर, सीहोर, हरदा, जबलपुर, देवास, नरसिंहपुर और रायसेन में मूंग की सबसे अधिक खरीदी देखने को मिली है। वहीं अब तक 2 लाख किसानों को एसएमएस भेजे जा चुके हैं। 8 अगस्त से मूंग और उड़द का उपार्जन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किया जा रहा है।

नर्मदापुरम जिले में एक लाख 17 हजार 603 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी हुई है। हरदा में 58 हजार 880 मीट्रिक टन, सीहोर में 52 हजार 993 मीट्रिक टन, नरसिंहपुर में 31 हजार 616 मीट्रिक टन, रायसेन में 24 हजार 368 मीट्रिक टन , जबलपुर में 18 हजार 337 मीट्रिक टन खरीदी, देवास में 14 हजार 779 मीट्रिक टन,सागर में 8 हजार 155 मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है।

बीज भण्डार™

जैन एग्रो एजेंसी

झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित
यह दीपावली आपके घर में सुख समृद्धि और
आशीर्वाद लेकर आये

दीपोत्सव

की हार्दिक शुभकामनाये

धर्मेन्द्र गिन्नारे
खरगोन

धर्मेन्द्र परमार (राजपूत)
राजपुर

रोहित कुशवाह
कसरावद

मोहन परमार
अंजड

कमलेश पाटीदार
मंडलेश्वर

नितेश परमार
मनावर

सुनील हम्मड
कुक्षी

अंकित पाटीदार
बडवाह

गोलू सिंह सोलंकी
धामनोद

दीपक जैन
जबलपुर

महिपाल ठाकुर
खंडवा

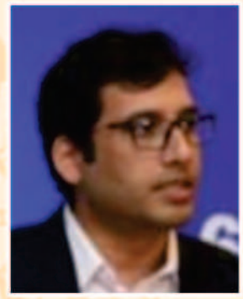
जीतेन्द्र मंडराह
छिन्दवाडा

रोहित जैन
बरगी

केशरसिंह परिहार
पुंजापुरा

मोहित जी
कला पीपल

हेड ऑफिस : जैन एग्रों एजेन्सी, नूतन नगर खरगोन (म.प्र.) +91 78794 28271

तेरहवा पुण्य स्मरण

वैभव जैन
स्वर्गवास 24.10.2009

अपने बिछड़े हुए लम्हों की
निशानी बनकर,
याद आँखों में उतर आती हैं
पानी बनकर
हम तो समझे थे
बहुत दूर हमें जाना हैं,
किसने सोचा था कि
चल दोगे कहानी बनकर

शोकाकुल

विनोद जैन- श्रीमती मीना,
विवेक - श्रीमती मुक्ति जैन (खरगोन)
विवेक बडजात्या- श्रीमती बरखा (बाकानेर)
रविन्द्र काला (इंदौर), अरुण धनोते (खरगोन)
एवं समस्त जैन परिवार

फर्म - बीज भंडार, जैन एग्रो एजेंसी, खरगोन

तेरहवा पुण्य स्मरण

मा. दक्ष जैन
स्वर्गवास 24.10.2009

अपने बिछड़े हुए लम्हों की
निशानी बनकर,
याद आँखों में उतर आती हैं
पानी बनकर
हम तो समझे थे
बहुत दूर हमें जाना हैं,
किसने सोचा था कि
चल दोगे कहानी बनकर

शोकाकुल

विनोद जैन- श्रीमती मीना,
विवेक - श्रीमती मुक्ति जैन (खरगोन)
विवेक बडजात्या- श्रीमती बरखा (बाकानेर)
रविन्द्र काला (इंदौर), अरुण धनोते (खरगोन)
एवं समस्त जैन परिवार

फर्म - बीज भंडार, जैन एग्रो एजेंसी, खरगोन

धान भंडारण में हेराफेरी, रघुवीरश्री गोदाम संचालक के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश

हलधर किसान। 98262.25025, भोपाल. प्रबंध संचालक वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन दीपक सक्सेना ने बताया कि कॉर्पोरेशन की जबलपुर जिले की शहपुरा शाखा अंतर्गत रघुवीरश्री गोदाम के भौतिक सत्यापन में एक करोड़ 31 लाख 29 हजार 144 रूपये की धान की बोरियाँ कम पाई गई थी। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक वेयर हाउसिंग जबलपुर को रघुवीरश्री गोदाम के संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं। संयुक्त भागीदारी योजना में विभागीय निरीक्षण दल द्वारा गोदाम का भौतिक सत्यापन 11 सितम्बर 2022 को किया गया।

गोदाम में गेहूँ, धान, चना, मूंग एवं अरहर की दाल भंडारित की गई थी। सत्यापन में गेहूं की 190 बोरियाँ अधिक और धान की 16 हजार 919 बोरी एवं चने की 31 बोरी कम पाई गईं। इस प्रकार 6 हजार 767 क्विंटल धान कम पाई गई। प्रबंध संचालक द्वारा हेराफेरी का मामला सामने आने पर गोदाम संचालक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण मानते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये

पिपलझोपा में राशन दुकान पर स्टॉक की जांच करते एसडीएम ढोके।

शाउमूदु में गेहूं, शक्कर कम तो चावल और मूंगदाल अधिक पायी गई

खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद में एसडीएम मिलिन्द ढोके ने शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपलझोपा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शाउमू दुकान के स्टॉक रजिस्टर और भौतिक सत्यापन में अन्तर पाया। शाउमूदू स्टॉक रजिस्टर अनुसार गेहूँ 6.51 क्विंटल और शक्कर 15 किलो कम पायी गई। वहीं चावल 15.62 क्विंटल और मूंगदाल 8.4 क्विंटल अधिक पायी गई। मौके पर दूकान का भौतिक सत्यापन पत्रक तैयार किया गया।

तहसीलदार ने सहकारी संस्था पिपलझोपा के प्रबंधक अश्पाक शेख एवं और शाउमू दुकान के विक्रेता कुलदीप पंवार द्वारा मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिया 11 (1) (2) एवं प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 10 का उल्लंघन करना पाया गया। यह अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है।

चावल के उत्पादन में 6 फीसदी गिरावट का अनुमान सात साल बाद थमा बंपर उत्पादन का सिलसिला

हलधर किसान।9826225025. दिल्ली- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2022.23 के लिए मुख्य खरीफफसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किया है। सात साल बाद खरीफसीजन में खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। अनुमान है कि कुल खाद्यान्न में 4 प्रतिशत और चावल के उत्पादन में चावल के उत्पादन में 6 फीसदी की गिरावट का अनुमान है।

कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि साल 2022.23 के खरीफ फसलों का उत्पादन 14.992 करोड़ टन रहेगा, जबकि पिछले साल के चौथे अनुमान के मुताबिक खरीफसीजन में 15.604 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। इस तरह पिछले साल के मुकाबले इस साल 61.2 लाख टन कम उत्पादन होने का अनुमान है, जो 3.9 प्रतिशत है।

2015.16 में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का सिलसिला टूटा था, लेकिन उसके बाद लगातार पिछले सालों के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही थी, परंतु एक बार फिर यह सिलसिला थमा है। इससे पहले बीते रबी सीजन में भी खाद्यान्न उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया गया था। साल 2021.22 के चौथे अग्रिम अनुमान में 15.968 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले सीजन 16.017 करोड़ टन उत्पादन के मुकाबले कम था। चालू खरीफसीजन में सबसे अधिक चावल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। अनुमान है कि 2022.23 में 10.499 करोड़ टन चावल का उत्पादन होगा, जबकि पिछले साल के चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफसीजन में चावल का 11.176 करोड़ टन उत्पादन हुआ। यानी कि इस साल 67.7 लाख टन उत्पादन कम हो सकता है, जो 6.05 प्रतिशत रहेगा।

खरीफ पोषक मोटे अनाज का उत्पादन 365.6 लाख टन अनुमानित है, जबकि पिछले सीजन में 509 लाख टन उत्पादन हुआ था। मोटे अनाज के उत्पादन में 28 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। मोटे अनाज के उत्पादन में साल 2009.10 के बाद इतनी ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। 2009.10 में 335.5 लाख टन उत्पादन हुआ था। वर्ष 2022.23 के दौरान कुल खरीफ दलहन उत्पादन 83.7 लाख टन अनुमानित है। पिछले सीजन में भी दलहन का उत्पादन इतना ही हुआ था।

वर्ष 2022.23 के दौरान देश में कुल खरीफ तिलहन उत्पादन 235.73 लाख टन अनुमानित है, जबकि पिछले साल 238.88 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। चालू खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट के लिए मुख्यतया 2022 के मानसून को दोषी माना जा रहा है। मानसून का असमान वितरण ने फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है।16 सितंबर 2022 तक के खरीफबुआई के आकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 18.90 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई कम हुई है, जबकि दलहन 5.58 लाख हेक्टेयरए तिलहन 1.32 लाख हेक्टेयर में बुआई कम हुई है।

जून से लेकर अगस्त तक उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में बारिश की भारी कमी का बुआई पर बड़ा असर पड़ा है। झारखंड में तो अब तक 9 लाख 37 हजार हेक्टेयर में धान की रोपाई कम हुई हैए जबकि मध्य प्रदेश में 6.32 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई कम हुई है। सरकार को पहले ही इस बात का अंदेशा था कि चावल का उत्पादन कम रह सकता है। इसलिए सरकार ने कुछ दिन पहले की चावल के निर्यात पर पाबंदियां लगा दी थी।

पांच साल के औसत से अधिक का अनुमान

हालांकि प्रेस सूचना ब्यूरो की ओर से जारी विज्ञप्ति में दावा किया गया कि वर्ष 2022.23 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान केवल खरीफके अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन विगत पांच वर्षों ;2016.17 से 2020.21 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 69.8 लाख टन अधिक है।

इसी तरह खरीफचावल का कुल उत्पादन में विगत पांच वर्षों;2016.17 से 2020.21 के 10.059 करोड़ टन औसत खरीफ चावल उत्पादन की तुलना में 44 लाख टन अधिक है।

मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2022.23 के दौरान देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 2.310 कराड़ टन अनुमानित है जो 1.989 करोड़ टन औसत मक्का उत्पादन की तुलना में 32.1 लाख टन अधिक है।

वर्ष 2022.23 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड 46.505 करोड़ टन अनुमानित है। 2022.23 के दौरान गन्ने का उत्पादन, 37.346 करोड़ टन औसत गन्ना उत्पादन की तुलना में 9.159 करोड़ टन अधिक है। कपास का उत्पादन 3.419 करोड़ गाठें (प्रति 170 किग्रा की गाठें) तथा पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 1.009 करोड़ गाठें (प्रति 180 किग्रा की गाठें) अनुमानित हैं।

दुधारू पशु खरीदने पशु पालकों को एसबीआई की चिन्हित शाखाएं देंगी ऋण

दुग्ध संघ और स्टेट बैंक ऑफइंडिया के मध्य हुआ करार

हलधर किसान। (9826225025) भोपाल. एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफइंडिया के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। इसमें दुग्ध संघों की वार्षिक सभाओं में बैंक के अधिकारी उपस्थित होकर पशु पालकों को पशु खरीदने के लिये ऋण दिलाने में सहायता करेंगे।

प्रबंध संचालक स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तरूण राठी ने बताया कि दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र की समितियों के पात्र सदस्यों को त्रि.पक्षीय अनुबंध के तहत 2,4,6 और 8 दुधारू पशु खरीदनें के लिये प्रदेश के प्रत्येक जिले में चयनित 3 से 4 बैंक शाखाओं द्वारा ऋण राशि उपलब्ध कराई जायेगी। हितग्राही को मार्जिन मनी के रूप में 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। दस लाख रूपये तक का मुद्रा लोन बिना कोलेस्ट्रल एवं एक लाख 60 हजार रूपये का नान मुद्रा लोन बिना कोलेस्ट्रल त्रि.पक्षीय अनुबंध के तहत हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जायेगा। हितग्राहियों को ऋण की अदायगी 36 किश्तों में करनी होगी।

पात्र हितग्राही को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन के साथ फोटो, आधार/पेनकार्ड, वोटर आईडी, दुग्ध समिति की सक्रीय सदस्यता का प्रमाण.पत्र और त्रि.पक्षीय अनुबंध (संबंधित बैंक

समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए 14 अक्टूबर तक करा सकेंगे पंजीयन

हलधर किसान। खरीफ सीजन 2022.23 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार व बाजरा समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। कृषक 15 अक्टूबर तक प्रातः 7 बजे से सांय 9 बजे तक पंजीयन करा सकते है। खरीब फसलों की उपार्जन के लिए खरगोन जिले में 11 किसान पंजीयन केन्द्र बनाए हैं। यह पंजीयन केन्द्र झिरन्या, महेश्वर, कसरावद, गोगांवा, बिस्टान रोड़ खरगोन, भगवानपुरा, भीकनगांव, करही, बड़वाह, सनावद तथा सेगांवा में स्थापित किए गए हैं।

पंजीयन केन्द्र शासकीय अवकाश एवं रविवार के दिन नहीं खुलेंगे। खरीफ फसलों के पंजीयन के लिए कृषक 50 रूपये शुल्क के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र, जनपद पंचायत में स्थित लोक सेवा केन्द्र तथा तहसील कार्योलयों एवं पूर्व वर्षों की भांति सहकारी समिति एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र या निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे के माध्यम से पंजीयन करा सकते है।

मत्स्य विकास के लिए 5 देशों के साथ साइन हुए एमओआई मछलियों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात की बढ़ेगी संभावना

हलधर किसान। 98262.25025

भोपाल. मत्स्य पालन के क्षेत्र में मार्केटिंगए ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 5 देशों तथा 8 राज्यों के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में मत्स्य उत्पादक, मत्स्य पालक एवं मत्स्य विक्रेताओं ने हिस्सा लिया।

कार्यशाला में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि आत्म.निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में मछली पालन क्षेत्र का अहम योगदान है। प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कारगर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के मत्स्य पालकों के सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिये भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिये अनेक लाभकारी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू कर उनका लाभ मत्स्य पालकों तक पहुंचाया जा रहा है।

सांसद शंकर लालवानी, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक रमेश मेंदोला, केन्द्र सरकार के मछली पालन विभाग के संयुक्त सचिव सागर मेहरा, राज्य सरकार के मछली पालन विभाग की प्रमुख सचिव

श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सुश्री आर. वनिता तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद के संचालक विजय कुमार भी उपस्थित थे।

मीठे पानी में उत्पादित हो रही मछलियां

कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के साथ प्रदेश में मीठे पानी में उत्पादित होने वाली मछली की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, और निर्यात के लिए नई संभावना पर भी विचार किया गया। कार्यशाला में जापान, वियतनाम, थाईलैंड, मॉरीशस तथा नेपाल के प्रतिनिधि भी विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इन देशों के प्रतिनिधियों ने मप्र सरकार के साथ एमओआई (मेमोरेंडम ऑफइंटरेस्ट) साइन किया। इससे प्रदेश में मछली उत्पादन को दोगुना किया जाने में मदद मिलेंगी। झींगा पालन को भी बढ़ावा मिलेगा और दो साल में झींगा उत्पादन दोगुना बढ़ाया जाएगा।

केन्द्रीय संयुक्त सचिव मत्स्य पालन सागर मेहरा ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये विशेष प्रयास हो रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद मत्स्य पालन की ग्रोथ में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2021.22 तक ग्रोथ दर 7 प्रतिशत तथा वर्ष 2022 में 10 प्रतिशत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार एवं आर्थिक उन्नति की अपार संभावनाएँ हैं।

कार्यशाला में बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2022 में मत्स्य बीज का उत्पादन 171 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राइ है, जिसे वर्ष 2023 तक 200 करोड़ किया जायेगा। इससे मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश आत्म.निर्भर बनेगा। अच्छी गुणवत्ता के बीज उत्पादित होने से मत्स्य कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध होंगे और मछली उत्पादन में गुणात्मक सुधार होगा। बताया गया कि प्रदेश में अभी तक मत्स्य पालकों के लिये 43 हजार 500 क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके है। इस कार्यशाला में मत्स्य महासंघ द्वारा मछुआ प्रोत्साहन राशि और आजीविका सहयोग योजना में 11 करोड़ की राशि का वितरण भी किया गया। साथ ही मछली उत्पादन और विक्रय के लिए मदद करने हेतु 50 मोटरसाइकिल, 100 किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजना का लाभ भी मछुआ युवाओं को वितरित किये गये। प्रदेश में नवाचार के रूप में मार्केटिंग के लिए स्मार्ट फिश पार्लर भी खोले जाएंगे।

14 से शुरु होगा अंतर्राष्ट्रीय मडई कृषि कार्निवाल, पोस्टर, ब्रोशर का किया विमोचन

हलधर किसान। 98262, 25025

छत्तीसगढ़- प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने अपने निवास कार्यालय में अक्टूबर माह में होने वाले 5 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 के पोस्टर और ब्रोशर का विमोचन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कृषि के विकास व किसानों की बेहतरी के कृतसंकल्प है। बता दें कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य शासन के कृषि विभाग व अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से इस पांच दिवसीय कार्निवल का 14 से 18 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले है। कृषि मंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी विकास व किसानों की समृद्धि और उनके विकास के लिए राज्य सरकार के साथ कदम मिलाकर कार्य कर रहा है।

कार्निवल में किसानों को मिलेंगी नई जानकारियां

पांच दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई के माध्यम से किसानों, विद्यार्थियों एवं सामान्य नागरिकों को कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन अनुसंधान, नवाचार, फ्सल प्रसंस्करण व मूल्य संर्वधन और उद्यमिता विकास के संबंध में नई.नई जानकारियां प्राप्त होंगी। इसके साथ ही आम लोगों को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित उन्नत कृषि अनुसंधानों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी करवाया जाएगा, ताकि वे कृषि की नवीन तकनीकों से अवगत हो सकेंगे।

विधायक विनय भगत, धर्मजीत सिंह और ममता चन्द्राकर के साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा गिरीश चंदेल उपस्थित थे। कुलपति ने कृषि मंत्री को बताया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा राज्य शासन के कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ बायोटेकनोलाजी प्रमोशन सोसायटी, अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपींस, नाबार्ड, कंसल्टेटिव ग्रुप आफ इन्टरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्चए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण एनएबीएल और अन्य संस्थाओं के सहयोग से 14 से 18 अक्टूबर तक अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 का आयोजन किया जाएगा।

एग्री कार्निवल में होगा कृषि मेला

इस आयोजन में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के निदेशक, कृषि वैज्ञानिक, विभिन्न कृषि उत्पाद निर्माता कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारी, स्टार्टअप्स उद्यमी और बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक शामिल होंगे। इस अवसर पर एक वृहद अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मेला सह .प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा।

विशेषज्ञों से सीखेंगे खेती के नुस्खे

इसके अलावा कृषि मड़ई में फसलों की नई किस्में, अधिक आय देने वाली वैकल्पिक फ्सलें, नवीन कृषि प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक और जैविक कृषि, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक, पशु पालन, मछली पालन और चारा उत्पादन, समन्वित फ्सल पोषक तत्व, कीट और बीमारी प्रबंधन, मृदा उर्वरता और मृदा स्वास्थ्य, वर्षा जल प्रबंधन और भू.जल संवर्धन, संरक्षित खेती, उन्नतशील कृषि यंत्र प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन आदि के संबंध में विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी जाएगी। इस दौरान कृषि आधारित स्टार्टअप्स के सफ्ल उद्यमियों द्वारा नवीन स्टार्टअप्स स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई में लगभग 20 हजार किसानों के शामिल होने की संभावना है।

साहसिक कार्य करने वाले होमगार्ड के जांबाज जवान अभिनंदनीय, इन्हें सलाम : गृहमंत्री डॉ. मिश्रा

हलधर किसान। 98262 25025, भोपाल- गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले होमगार्ड के 45 जांबाज अधिकारी.कर्मचारियों को सम्मानित किया।

उन्होंने कहा है कि होमगार्ड के जवान आपदाओं के निराकरण के लिये हर समय तत्पर रहते हैं। आपदा एवं राहत के कार्य में प्रत्येक मौसम में स्वयं की जान की परवाह किये बगैर होमगार्ड के जवान कार्य करते हैं। मैं इन जाँबाज जवानों का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। समारोह में आधुनिक संसाधनों से लैस बचाव कार्य में उपयोग में आने वाली 46 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और 15 मिनी ट्रक वाहनों की चाबियाँ प्रदान की गई। गृहमंत्री ने कहा कि होमगार्ड के जवानों की सेवाएं सराहनीय हैं। सरकार द्वारा उनके हौसले और जुनून को देखते हुए सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। निरंतर उनकी माँगों को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। डीजी होमगार्ड पवन कुमार जैन ने जवानों के सेवा कार्य के जज्बे को सलाम किया।

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, एडीजी डीपी गुप्ता, एडीजी अशोक अवस्थी, एडीजी लोकायुक्त अजय शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

महानिदेशक होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन श्री जैन ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न जिलों के 45 अधिकारी.कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इनमें भोपाल और विदिशा के 6.6, छतरपुर, सीहोर और रायसेन के 5.5, कटनी, अशोकनगर और गुना के 4.4, आगर.मालवा और बालाघाट के 3.3 अधिकारी शामिल हैं।

Chamunda SEED

समस्त किसान भाइयों एवं देशवासियों को
दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाये

हाईब्रीड भिंडी -आराध्या

- लम्बी तोड़ाई बार बार लगातार
- बाज़ार की पहली पसंद
- हरे रंग की चमकदार फल
- वायरस के प्रति सहनशील
- आसान एवं सरल तोड़ाई

Chamunda Agro Pvt. Ltd.
A-222, SS Rana Road, Majils Park, Delhi-110033
Phone : 011- 27675466
email : info@chamundaagro.com

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन। Titel Code. MPHIN/2022/37675, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।